बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 106 ● नई दिल्ली ● बुधवार 04 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

शब ए बरात: खूब चला इबादत का सिलसिला, जगह-जगह हुए जलसे

मुरादाबाद। शब-ए-बरात के मौके पर महानगर में इबादत का जोर रहा। मस्जिदें गुलजार रहीं, तो घरों में भी इबादत का सिलसिला चला। लोगों ने कब्रिस्तानों में पहुंचकर बुजुर्गों की कब्रों पर चिराग किया और फातिहा पढ़कर उनकी मगफिरत के लिए दुआ की। मस्जिदों एवं घरों में इबादत का सिलसिला रात भर चलता रहा। घरों में नफ्ली निमाज भी की गई। वह रात जिसके लिये कहा जाता है कि इबादत करो और दुआ मांगो तो कबूल होती है, शब-ए-बाअत कही जाती है। मुरादाबाद में मंगलवार को शब-ए-बरात को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। घरों में सुबह से ही इबादत की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मर्द ही नहीं घरों में खवातीन भी शब ए बरात को रात इबादत की तैयारियों में जुटी रहीं।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बजट में कटौती, कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार के सामने रखे कई सवाल

नई दिल्ली । केन्द्रीय बजट में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित राशि में कटौती को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि बजट में की गई यह कटौती न सिर्फ सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर करती है, बल्कि दिल्लीवासियों को जहरीली हवा से राहत देने के दावों की पोल भी खोलती है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि केन्द्रीय बजट में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित राशि में 209 करोड़ रुपये की कटौती भाजपा की मोदी सरकार की उदासीनता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि देश भर के लिए पिछले वर्ष 1300 करोड़ रुपये का बजट था, जिसे इस वर्ष घटाकर 1091 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह फैसला प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने वाला है. देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि राजधानी दिल्ली में पहले ही प्रदूषण नियंत्रण में नाकाम रही रेखा गुप्ता सरकार के बाद अब केन्द्र सरकार भी दिल्लीवासियों को राहत देने के मूड में नहीं दिख रही है. उन्होंने कहा कि जहरीली और दमघोंटू हवा से जूझ रही दिल्ली के लिए सीएक्यूएम को केवल 35.26 करोड़ रुपये आवंटित करना बेहद नाकाफी है, जबकि दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर है. उन्होंने कहा कि भारी बारिश और तेज हवाओं के बावजूद पूरे जनवरी महीने में दिल्ली का एक्यूआई एक भी दिन 100 से नीचे नहीं गया. यह राजधानी की

खराब हवा की भयावह स्थिति को साफ तौर पर दर्शाता है. इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के बजट में कटौती और इस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री की चुप्पी दिल्लीवासियों के साथ विश्वासघात है. देवेन्द्र यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने प्रदूषण को जड़ से खत्म करने का दावा किया था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. पिछले एक वर्ष में दिल्ली की हवा हर दिन और अधिक जहरीली होती गई है और राजधानी धीरे-धीरे गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण देश और दिल्ली में हर साल लाखों लोगों की मौत होती है, इसके बावजूद सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गंभीर नहीं है. बजट में कटौती से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और गहरा सकता है, क्योंकि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकताओं में कभी शामिल नहीं रहा. देवेन्द्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत देश के 82 प्रदूषित शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों पर बजट कटौती का सीधा और नकारात्मक असर पड़ेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि रेखा सरकार ने दिल्ली में अब तक कोई नई और ठोस कार्ययोजना लागू नहीं की है और केवल पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों का अनुसरण कर रही है. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संसदीय पैनल को केवल चिंता जताने के बजाय एक ठोस योजना बनाकर लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए. देवेन्द्र यादव ने बताया कि बजट में कटौती का एक बड़ा कारण फंड का सही उपयोग न होना है. वर्ष 2024-25 में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित 858 करोड़ रुपये में से 31 जनवरी 2025 तक एक प्रतिशत से भी कम, यानी सिर्फ 7.22 करोड़ रुपये खर्च होना केन्द्र सरकार की प्रशासनिक गैर जिम्मेदारी को उजागर करता है.

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली एनसीआर द्वारा आयोजित वार्षिक मेल-मिलाप कार्यक्रम

नई दिल्ली ।

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली एनसीआर द्वारा राजेंद्र भवन में आयोजित वार्षिक मेल-मिलाप कार्यक्रम में डोगरी-पहाड़ी भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और एकता का स्वर ज़ोरदार तरीके से गूंजा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत रह चुके, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. कर्ण सिंह ने कहा कि डोगरा समाज को कांगड़ा और चंबा जैसे पड़ोसी पहाड़ी-भाषी क्षेत्रों के साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक एकता को मज़बूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुभाषिक होना समय की ज़रूरत है, लेकिन मातृभाषा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि नई पीढ़ी को डोगरी बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया गया तो यह भाषा आने वाले समय में संकट में पड़ सकती है। डॉ.सिंह ने भाषा संरक्षण में परिवारों, विशेष रूप से माताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए डोगरों से एकजुट, प्रगतिशील और दूरदर्शी बने रहने की अपील की। उन्होंने इस आयोजन के लिए सुदेश डोगरा और समस्त आयोजक टीम को बधाई भी दी। लोकप्रिय डोगरी-हिमाचली लोकगीत माये निं मेरिये, जम्मूऐ दी राहे, चंबा कितनी क दूर में कथित छेड़छाड़ के विरोध में प्रसिद्ध गायक धीरज शर्मा ने गीत को उसके मूल शब्दों में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में

ज्योति गुप्ता सहित अन्य कलाकारों ने भी भाग लिया। एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर जम्मू के प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों की चुप्पी पर निराशा व्यक्त की, जबकि लोकगीतों की सांस्कृतिक चिंताओं की हिफाजत में आवाज़ उठाने वाले हिमाचली कलाकारों की सराहना की। वरिष्ठ पत्रकार

कार्यक्रम में डोगरी-पहाड़ी भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और एकता का स्वर ज़ोरदार तरीके से गूंजा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत रह चुके, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. कर्ण सिंह ने कहा कि डोगरा समाज को कांगड़ा और चंबा जैसे पड़ोसी पहाड़ी-भाषी क्षेत्रों के साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक एकता को मज़बूत करना चाहिए।

और भाषा कार्यकर्ता रमन केसर ने कहा कि लोकगीतों के साथ छेड़छाड़ पश्चिमी पहाड़ी और डोगरी को अलग-अलग दिखाने की चेष्टा है, जिसका एसोसिएशन रचनात्मक और सशक्त ढंग से विरोध करेगी। इस अवसर पर रोहित महाजन, क्लस्टर हेड, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को ट्रॉफियां भेंट कर के सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजन में कैलाशपति शर्मा, सुदेश डोगरा, जगदीश शर्मा , कुलबीर सिंह , कर्नल सुनील शर्मा, नेहा शर्मा, सतपाल शर्मा और बोधराज ठाकुर, राज रैना जी का विशेष योगदान रहा। डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन पिछले चार वर्षों से लोहड़ी के अवसर पर लगातार यह आयोजन कर रही है। एसोसिएशन ने स्वयं को राजनीति से दूर रखा हुआ है और समाजी-सांस्कृतिक कार्यों में लगी हुई है।

नई सड़कें, सुरंग और ई-बस, 27,328 करोड़ के प्रोजेक्ट्स से बदलेगी दिल्ली, बिधूड़ी बोले- जाम से राहत तय

नई दिल्ली।

दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रेसवार्ता में कहा कि केंद्रीय बजट में दिल्ली की चिंता की गई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने डीटीसी को बर्बाद कर दिया। एक भी बस नहीं खरीदी। कोई भी नया फ्लाईओवर नहीं बनाया। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण दूर करने के लिए राजधानी में यातायात सुगम और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए बजट में ध्यान रखा गया है। 27328 करोड़ रुपया दिल्ली के अंदर ट्रैफिक सिस्टम सुधारने के लिए खर्च होंगे। नए सड़क बनेंगे, पुरानी सड़कों की दशा सुधरेगी। उन्होंने कहा, वसंत कुंज से त्रिमूर्ति तक पांच किलोमीटर सुरंग के लिए 3500 करोड़ रुपये, एम्स से महिपालपुर तक सड़क के लिए पांच हजार करोड़, कालिंदीकुंज पर इंटरचेंज बनाने के लिए पांच सौ करोड़। मथुरा लाइन को चौड़ा और लाल बत्ती खत्म करने के लिए 513 करोड़ रुपये, महरौली - गुरुग्राम रोड पर भी लाल बत्ती समाप्त होगी। इसके साथ ही कई अन्य सड़कों का भी निर्माण हो रहा है। इससे यात्रा सुगम होने के साथ जाम की समस्या भी कम होगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में रेलवे परियोजनाओं पर 2711 करोड़ खर्च होंगे, नमो ट्रेन और मेट्रो निर्माण को गति देने के लिए फंड आवंटित किए गए हैं। बजट में शहरों के लिए चार हजार इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इसमें से दिल्ली को भी बसें मिलेंगी। उन्होंने कहा, केजरीवाल सरकार में दिल्ली देहात की अनदेखी की गई थी। के केंद्र सरकार ने लोक सभा चुनाव के बाद गांवों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए थे। इस बार बजट में 540 करोड़ रुपये दिए हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने भी दो हजार करोड़ रुपये दिए हैं।

मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, पंजाब में हुई एफआईआर को विशेषाधिकार समिति को भेजने का किया अनुरोध

नई दिल्ली। कैबिनेट कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर अपने खिलाफ पंजाब में दर्ज एफआईआर मामले में कार्यवाही का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि इकबाल सिंह द्वारा की गई शिकायत तथा उसके आधार पर जालंधर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर सहित की गई कार्रवाई संविधान के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण की अवहेलना है तथा यह विधानसभा के विशेषाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि विधानसभा की कार्यवाही के पर्याप्त रूप से सत्य विवरण के प्रकाशन के संबंध में आपराधिक कार्यवाही आरंभ किया जाना विधायिका की गरिमा, स्वतंत्रता एवं अधिकार में हस्तक्षेप के समान है। अतः उन्होंने इस पूरे प्रकरण को अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लेकर विशेषाधिकार समिति

को संदर्भित करने का अनुरोध किया है, ताकि समुचित जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अपने पत्र में मिश्रा ने संविधान के अनुछेद 361ए का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद अथवा राय विधानमंडल की कार्यवाही के पर्याप्त रूप से सत्य विवरण के प्रकाशन के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, जब तक यह सिद्ध न हो कि उक्त प्रकाशन दुर्भावना से किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उक्त अनुछेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह संवैधानिक संरक्षण संसद अथवा राय विधानमंडल के किसी भी सदन की गुप्त बैठकों की कार्यवाही से संबंधित रिपोर्टों के प्रकाशन पर लागू नहीं होता। मिश्रा ने पत्र में स्मरण कराया कि गत 6 जनवरी को सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा सिख गुरुओं के विरुद्ध टिप्पणी किए जाने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। इसके पश्चात नौ जनवरी को मुख्य सचेतक अभय वर्मा द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जालंधर पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है कि उन्होंने विधानसभा कार्यवाही का एक कथित रूप से संपादित (डाक्टर्ड) वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है।

बारिश और ठंड की वापसी: साल 2022 के बाद सबसे ठंडा रहा फरवरी का दूसरा दिन, आज कोहरे का यलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली ।

पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने के बाद बीते कई दिन से दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश और ठंड की वापसी के बाद अब कोहरे का भी प्रकोप झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए कोहरे व धुंध का यलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में दिन का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह के समय कई जगह पर हल्का और कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। इसके अलावा, साल 2022 के बाद फरवरी माह सबसे ठंडा रहा। साल 2023 में पूरे महीने का औसत अधिकतम पारा 28.2 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं, 2024 में 24.4 और 2025 में 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रविवार देर रात से ही कोहरे ने पूरे आसमान को अपने आगोश में ले लिया था। ऐसे में इसका असर सोमवार की सुबह देखने को मिला। तड़के ही कोहरे व धुंध छाई रही। इससे दृश्यता भी कम रही। इसी बीच तेज बर्फीली हवाओं ने लोगों को खासा परेशान किया और दिल्ली में ठिठुरन बढ़ा दी। दिल्ली में अगले छह दिनों तक मौसम में यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। राजधानी में हवा की गति तेज होने से प्रदूषण खराब श्रेणी में हवा बरकरार है। ऐसे में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 210 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है। इसमें शनिवार की तुलना में 55 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर, एनसीआर में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 279 दर्ज किया गया, यह हवा की खराब श्रेणी है। नोएडा में 238, गुरुग्राम में 191 और ग्रेटर नोएडा में 228 एक्यूआई दर्ज किया गया। फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 163 दर्ज किया गया। यह हवा की मध्यम श्रेणी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार, वाहन से होने वाला प्रदूषण 12.27 फीसदी रहा। पेरिफेरल उद्योग से 10.19, आवासीय इलाकों से 3.11, निर्माण गतिविधियों से 2.09 और कूड़ा जलाने से होने वाले प्रदूषण की 1.18 फीसदी की भागीदारी रही। शाम चार बजे हवा में पीएम10 की मात्रा 166.2 और पीएम2.5 की मात्रा 94 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पूर्वानुमान है कि बुधवार तक हवा इसी श्रेणी में बरकरार रहेगी।

कुवारों के लिए फरवरी माह में पड़ने वाला यह प्यार का त्यौहार

वैलेंटाइन डे पर महिलाओं में सम्मोहक और आकर्षक दिखने की चाह प्राकृतिक होती है / प्यार के बंधन में बन्धे दम्पतियों और प्यार की चाहत पालने वाले कुवारों के लिए फरवरी माह में पड़ने वाला यह प्यार का त्यौहार काफी मायने रखता है / चाहे आप नए बन्धन में बन्धे हों या फिर लम्बे समय से एक दूजे के लिए समर्पित हों ,यह दिन एक दूसरे के प्रति समर्पण ,परिपक्वता दिखाने का बेहतरीन अवसर है / यदि आप अपने पति /प्रियतम से दूर हैं तो आप उन्हें ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से उनकी पसन्द की गिफ्ट भेज सकती हैं / इस समय में मार्किट में वैलेंटाइन डे की गिफ्ट्स की काफी भरमार है /आप उन्हें उनकी पसन्द की चॉकलेट ट्रफल ,मिल्क चॉकलेट , डार्क चॉकलेट ,स्ट्रॉबेरी या देसी लड्डू /मिठाई भेज सकती हैं / यदि आप अलग रहती हैं तो अपने प्रियतम को एक सरप्राइज गिफ्ट भेज कर अपने प्यार की परिपक्वता दर्शा सकती हैं / यदि आप इस असमंजस में हैं कि क्या भेजा जाये तो मेरी सलाह के अनुसार इस मौके पर क्लासिकल पेंटिंग , आर्ट ऑब्जेक्ट, छाया चित्र या फूलों का गुलदस्ता बेहतर रहेगा / आप नजदीकी पर्यटन स्थल पर जा सकती हैं / आप आजकल के ठन्डे मौसम में दूर निर्जन जंगल /चिड़िया घर /पक्षी अभ्यारण में एकांत के कुछ पल अपने प्रियतम के साथ गुजार सकती हैं / आप किसी प्राकृतिक स्थल या निर्जन स्थल पर लम्बी यात्रा पर भी जा सकती हैं जहां आप एक दूसरे के ज्यादा नजदीकी का अहसास कर सकें और भावनात्मक रूप से 'जुड़ सकें' / वैलेंटाइन डे पर आप सुंदर मधुर , आकर्षक या रोमांटिक दिखना पसंद करती हैं तो इस खास दिन दमकती त्वचा , रेशमी घने बालों , आकर्षक चेहरे , तथा व्यक्तित्व का धनी बनने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी //इस खास दिन प्राकृतिक तथा दमकती त्वचा पाने के लिए साधारण ब्यूटी टिप्स की मदद से आप इस दिन को बेहतरीन खास दिन बना सकती हैं मलाई और हल्दी - हल्दी तथा मलाई का मिश्रण बना कर इसे चेहरे पर लगा कर दस मिनट बाद चेहरे को साफ , ताजे पानी से धो डालिये इससे आपकी त्वचा साफ हो जाएगी तथा चेहरा पर आभा लौट आएगी /चेहरे की रंगत चमकाने के लिए बेसन, चंदन तथा हल्दी का फेस पैक बना कर रोजाना चेहरे पर प्रयोग करने से आपकी त्वचा साफ होगी तथा चेहरे की रंगत में निखार आएगा / गुलाब जल में काटन वूल पैड डुबो कर इसे फ्रीज में रखें। पहले इससे त्वचा को धोएं तथा बाद में इससे त्वचा को धीरे-धीरे सहलाएं। इस मिश्रण को गालों पर उपरी तथा नीचली दशा में हल्के-हल्के सहलाते हुए लगाएं, तथा प्रत्येक स्ट्रोक को कनपटी तक ले जाएं। इस मिश्रण को माथे पर लगाते समय मध्य बिन्दु से शुरू करके तथा दोनों तरफ बाहरी दिशा में कनपटी तक घुमाएं। ठोड़ी के मामले में इसे घुमावदार तरीके से लगाएं। इसके बाद गुलाब जल में भीगे काटनवूल पैड से त्वचा को तेजी से थपथपाइए। ''पिक मी अप'' फेस मास्क से आपकी त्वचा साफ तथा चमकीली बन सकती है। शहद में सफेद अण्डा मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएं तथा 20 मिनट बाद ताजे साफ पानी से धो डालिए। अगर आपकी त्वचा अत्याधिक शुष्क है तो शहद में अण्डे का पीला भाग (योक) तथा थोड़ा सा दूध मिला लीजिए तथा इस मिश्रण को 20 मिनट तक चेहरे पर लगाने के बाद ताजे साफ पानी से धो डालिए। चेहरे को साफ करने के बाद गुलाब जल में भीगे काटन वूल की मदद से त्वचा को दबाइए। फेशियल स्क्रब का उपयोग कीजिए। इससे त्वचा से मृत कोशिकाएं हट जाती हैं जिससे त्वचा चमक उठती है। अखरोट के पाऊडर तथा एक चम्मच शहद तथा एक चम्मच दही को मिलाकर फेशियल स्क्रब बना लीजिए इस मिश्रण को कुछ समय तक चेहरे पर लगा रहने दीजिए। इसके पश्चात चेहरे की गोलाकार स्वरूप में हल्के से मसाज कीजिए तथा बाद में स्वच्छ पानी से धो डालिए। सूखी तथा पीसी हुई कड़ी पत्ता को दो चम्मच पानी में शामिल किया जा सकता है तथा इससे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। कड़ी पत्ता को दो चम्मच जई या चोकर, दो चम्मच गुलाब जल तथा एक चम्मच दही में मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए जोकि टपकना नहीं चाहिए। इस पेस्ट को आंखों तथा होठों को छोड़कर बाकी चेहरे पर लगा लीजिए तथा आधा घण्टा बाद चेहरे को धो डालिए। चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए फ्रूट पैक काफी सहायक सिद्ध होते हैं तथा इन्हें चेहरे पर प्रतिदिन लगाया जा सकता है। सेब को पीसकर इसे पके पपीते की लुग्दी तथा मसले हुए केले में मिलाकर मिश्रण बना लें तथा इस मिश्रण में दही या नींबू जूस भी मिलाया जा सकता है। इस मिश्रण को चेहरे पर आधा घंटा तक लगा रहने दीजिए तथा बाद में चेहरे को साफ पानी से धो डालिए। इससे चेहरे की लालिमा बढ़ती है तथा चेहरे की कालिख को भी दूर करता है तथा त्वचा को मुलायम बनाता है। तैलीय त्वचा के लिए मुलतानी मिट्टी को गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट बना लें तथा इस पेस्ट को होठों तथा आंखों के इस गिर्द क्षेत्र को छोड़कर बाकी चेहरे पर लगा लीजिए तथा जब यह पेस्ट सूख जाए तो इसे ताजे पानी से धो डालिए। मिश्रित त्वचा के लिए इस मास्क को त्वचा के तैलीय भाग पर ही लगाइए। सामान्य त्वचा के लिए मुलतानी मिट्टी में शहद तथा दही मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने के बाद 30 मिनट बाद चेहरे को ताजे पानी से धो डालिए। चमकती त्वचा पाने के लिए सभी सौंदर्यों को साफ वस्त्र में बांध लीजिए तथा इस वस्त्र को हल्के से गिला कर लीजिए तथा इस कपड़े के बैग को नहाती बार त्वचा से रगड़िए। पाऊडर, दूध, बादाम, चावल पाऊडर तथा गुलाब की पत्तियों को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लीजिए। इस मिश्रण को त्वचा पर लगाने से त्वचा साफ हो कर मुलायम, चमकीली तथा आकर्षक बन जाती है। इससे शरीर में प्राकृतिक सुगन्ध तथा ताजगी का अहसास होता है तथा रेशम जैसी कोमलता का अहसास होता है। हमेशा यह ध्यान रखें की इस दिन का माहौल हल्का और रंगीन मिजाज रहना चाहिए / इस दिन अपने पति या प्रियतम से घरेलू आर्थिक हालात , बच्चों की पढ़ाई या पड़ोसियों से झगड़ों आदि पर चर्चा से परहेज करें ताकि उनका मूड खराब ना हो। -लेखिका अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ है तथा हर्बल क्वीन के रूप में लोकप्रिय है।

भारत में वीआईपी मूवमेंट के लिए नियम-कानून का अंबार है, फिर भी चूक कैसे

महाराष्ट्र के प्रखर नेता अजित दादा को हमने खो दिया। बस उनकी यादें शेष रह गई है। नागपुर में पिछले विधानसभा सत्र के दौरान महाराष्ट्र के मंत्रियों और विधायकों के लिए मैंने सम्मान भोज आयोजित किया था। दादा आए थे। बड़ी खुशमिजाजी से मिले, आमतौर पर गंभीर रहने वाले अजित दादा की आंखों में उस दिन गजब की चमक थी। व्यक्तित्व में उल्लास झलक रहा था। उन्होंने कहा कि जिस बिल्डिंग में आप रहते है वहीं रहने मेरे सुपुत्र पार्थ भी आ रहे है। मैं घर देखने आने वाला हूं। फिर साथ बैठेंगे, भोजन करेंगे और खूब गप्पें लड़ाएंगे। मैंने मजाक में कहा कि दादा लड़ेंगे-लड़ाएंगे नहीं, खुशियां मनाएंगे। नियति के दस्तूर का क्या कहें, कहानी बनते-बनते अधूरी रह गई। दादा यादों के इंद्रधनुष का हिस्सा बन गए। जाने वाले कब लौट कर आते हैं? बस यादें रह जाती हैं। अपने राजनीतिक गुरु और चाचा शरदचंद पवार के नक्शे-कदम पर उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ा। फर्क बस इतना था कि शरदचंद पवार मुस्कुरा कर राजनीति करते है और अजित दादा बेबाक थे। हां तो हां, ना तो ना! पवार साहब की तरह ही सूर्योदय के साथ अजित दादा की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। पहली बैठक का समय होता था सुबह 7 बजे! ऐसी बहुत सी बातें है जो उन्हें पसंद करने का कारण थीं।

मुंबई में शनिवार या रविवार को कितना भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, वे शामिल नहीं होते थे क्योंकि इनमें से एक पुणे और दूसरा दिन बारामती के लिए आरक्षित रहता था। दादा के साथ की और भी बहुत सी यादें हैं लेकिन इस वक्त मैं इस सोच से उबर नहीं पा रहा हूं कि हवाई यात्राएं इतनी असुरक्षित क्यों हो रही हैं। भारत में हवाई यात्रा की सुरक्षा को हम सब बहुत बेहतर कहते है। इसके समर्थन में हमारे पास बहुत से कागजी आंकड़े भी है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में हम 112 से उठ कर 55 वें स्थान तक पहुंच चुके है, मगर मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि चूक कहां हो रही है? जब हम सड़क पर यात्रा करते हैं तो भीषण दुर्घटना में भी बचने की संभावनाएं बनी रहती है लेकिन हवा में तो एक छोटी सी चूक भी सभी यात्रियों के लिए मौत का कारण बन जाती है। भारत में वीआईपी मूवमेंट के लिए नियम-कानून का अंबार है, फिर भी चूक कैसे हो जाती है। आखिर ऐसी दुर्घटनाओं में हमने कितने लोगों को खोया है। लंबी सूची है। होमी भाभा, बिपिन रावत, संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, विजय रूपाणी, ओपी जिंदल, जी. एम. सी. बालयोगी, वाई. एस. आर. रेड्डी, दोरजी खांडू और साहब्रिन संगमा जैसे अनेक प्रमुख व्यक्तियों के नाम शामिल है। वैसे प्रसंगवश बता दें कि 1965 की जंग में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता के विमान को पाकिस्तान ने सैन्य विमान समझ कर मार गिराया था। खैर, वह तो मामला ही अलग था। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो चले गए। विमान दुर्घटना से बाल-बाल बचने वालों में वसंतराव नाईक से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक की लंबी सूची है। जब राहुल गांधी आंध्रप्रदेश के चुनावी दौरे पर थे तब मैंने महसूस किया कि लैंड करते वक्त धूल का ऐसा गुब्बार उठा कि हैलिकॉप्टर दिख ही नहीं रहा था। वह दृश्य देखकर मैं घबरा गया था। एक और घटना बताता हूं। मैं और मेरे अनुज राजेंद्र दर्डा हैलिकॉप्टर से मुंबई से पुणे जा रहे थे। कुल जमा दस-पंद्रह मिनट की यात्रा थी लेकिन इतना कोहरा था, इतना प्रदूषण था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस मार्ग पर कई पहाड़ है और ऊंची इमारतें हैं। हमने भगवान का नाम लेते वह यात्रा की। आए दिन हमें यह खबर मिलती रहती है कि कहीं विमान से पक्षी टकरा गया तो कहीं रनवे पर कुत्ता आ गया। कई पायलट्स ने तो यहां तक शिकायत की है कि लेजर बीम के कारण भी उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब अजित दादा के चार्टर्ड विमान की दुर्घटना को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि विमान में भी खामियां थीं। इसके अलावा बारामती एयरपोर्ट पर न तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है और न ही इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है। स्थानीय फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर रेडियो कम्युनिकेशन संभालते हैं। पायलट को रनवे तलाशने के लिए सूरज के सामने देखना पड़ रहा था। सूरज की चमक ने भी चकमा दिया होगा और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर सामने आ रही है, वह है पायलट कैप्टन सुमित कपूर का मदिरा प्रेम। दो बार ऐसे मौके आए थे जब फ्लाइट से पूर्व उन्हें नशे में पाया गया और डीजीसीए ने उन्हें तीन साल के लिए निलंबित भी किया था। सवाल है कि ऐसे कैप्टन के हाथों में प्लेन क्यों दिया गया? कमर्शियल पायलट की नींद सात घंटे हुई है या नहीं या फिर वह नशे में तो नहीं है, इसकी जांच व्यापक तौर पर होती है लेकिन चार्टर्ड एयरक्राफ्ट और हैलिकॉप्टर के मामले में क्या इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है? मैं सोच रहा हूं कि अत्यंत छोटे विमानतलों पर भी यदि सुरक्षा की व्यवस्था माकूल नहीं है तो फिर उन विमानतलों को संचालित ही क्यों किया जा रहा है? भले ही किसी विमानतल पर महीने-दो महीने में एक विमान ही उतरे लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था तो वैसी ही होनी चाहिए जैसे बड़े विमानतलों पर होती है, वैसे तो देश के सारे राज्यों को अपने विमानतलों पर समुचित सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए लेकिन विकसित राज्य महाराष्ट्र को इस मामले में नजीर पेश करनी चाहिए। अजित दादा तो चले गए, उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता लेकिन यह तो सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी हवाई दुर्घटना फिर कभी न हो। फिर किसी की जान न जाए। अजित दादा हम आपको कभी भुला न पाएंगे। अलविदा!

सम्पादकीय...

अमेरिका बल प्रयोग

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव से अशांति का नया दौर शुरू हो सकता है। अशांति का यह दौर ईरान के धार्मिक शासन के सामने गहरी आर्थिक कमजोरियों और राजनीतिक जोखिमों के बीच शुरू होगा। अमेरिका बल प्रयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी युद्ध पोत और नौसैनिक बल ईरान की घेराबंदी कर चुके है। अमेरिका के लड़ाकू विमान जार्डन के एयरफोर्स बेस पर पहुंच चुके है। इसके अलावा जार्डन, कतर और हिन्द महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के सैन्य ठिकानों तक पहुंचने वाले विमानों की संख्या भी बढ़ रही है। तनाव बढ़ने पर अमेरिका किसी भी क्षण ईरान पर हमला कर सकता है। 2 महीने पहले ही ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिनों के भीषण युद्ध से खुद को बचाया था। नव वर्ष की शुरूआत होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को धमकी दी थी कि यदि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका बल प्रयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान और इजराइल के बीच पिछले वर्ष जून के युद्ध के दौरान ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमले का आदेश दिया था। इसके बाद दोनों देशों में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। यूरोपिय यूनियन ने ईरान की सेना आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसके बाद ईरानी संसद से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इस तस्वीर में ईरान के सभी सांसद अपनी सेना की वर्दी पहने नजर आए। यह तस्वीर सीधे तौर पर ट्रम्प को एक चुनौती है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ट्रम्प को चेतावनी दी है कि कोई भी नया युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाएगा। ईरान अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। खामेनेई की चेतावनी के बाद ट्रम्प उम्मीद लगाए बैठे है कि दबाव के चलते ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार होगा। ट्रम्प ने यह भी कहा है कि अमेरिका कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है और सभी विकल्प खुले रखे गए है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उनकी सरकार बातचीत पर ध्यान दे रही है और उनका लक्ष्य ऐसा समझौता करना है जिसमें ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समझौता नहीं होता तो आगे की स्थिति साफ हो जाएगी। ट्रम्प ने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए कोई स्वीकार्य समाधान निकल सकता है। उनके मुताबिक, ऐसा समझौता संभव है जो परमाणु हथियारों के बिना हो और सभी पक्षों के लिए संतोषजनक हो। दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर भी मिले-जुले संकेत मिल रहे है। हालांकि ईरान का कहना है कि वह निष्पक्ष बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन वह अपनी रक्षा क्षमताओं पर किसी तरह की पाबंदी स्वीकार नहीं करेगा। खामेनेई लगातार यह आरोप लगाते आ रहे है कि ईरान में हुए विरोध-प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल की तख्तापलट की साजिश है और वे अमेरिकी सैन्य धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही निशाने पर रहा है। ट्रम्प के बयानों से ऐसा आभास मिलता है कि वह ईरान से सीधे युद्ध में उलझना नहीं चाहते। इसलिए वे फिलहाल सैन्य कार्रवाई से बचना चाहते है।

भारतीय समाज में लिव-इन को लेकर आज भी गहरी असहमति

भारत, जहाँ विवाह को केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का पवित्र बंधन और एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, वहीं लिव-इन रिलेशनशिप (बिना विवाह साथ रहना) आज भी एक वैचारिक युद्ध का मैदान बना हुआ है। एक ओर सनातन परंपराओं की जड़ें हैं, तो दूसरी ओर आधुनिकता की उड़ान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सनातन धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। यह केवल शारीरिक या कानूनी समझौता नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का एक माध्यम है।पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार, विवाह व्यक्ति को सामाजिक उत्तरदायित्व और अनुशासन सिखाता है।भारतीय संस्कारों में अग्नि और ईश्वरीय शक्तियों को साक्षी मानकर किए गए वादे रिश्ते को पवित्रता और मजबूती प्रदान करते हैं।सनातन परंपरा में परिवार को समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है, जिसे लिव-इन संबंधों में अक्सर गौण कर दिया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से महानगरों में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन तेजी से बढ़ा है। जो भारत के संस्कारों और हिंदू विवाह के मान्यताओं को खंडित करता है, और कहीं ना कहीं भारतीय सनातन के स्थापित प्रतिमानों को चुनौती देता है। लेकिन युवा पीढ़ी इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क देती है। युवाओं का मानना है कि जीवनभर के बंधन में बंधने से पहले एक-दूसरे के स्वभाव और आदतों को समझना जरूरी है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार को आधार बनाकर इसे व्यक्तिगत चुनाव माना जाता है। विवाह टूटने की स्थिति में होने वाली लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और सामाजिक बदनामी के डर से बचने के लिए इसे एक ट्रायल के रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में लिव-इन को लेकर आज भी गहरी असहमति है, जिसके पीछे कई कारण है। सामाजिक असुरक्षा: लिव-इन में अक्सर महिलाओं को वह सामाजिक सुरक्षा और सम्मान नहीं मिल पाता जो एक पत्नी को प्राप्त होता है। बच्चों का भविष्य: सनातन धर्म में संतान का जन्म और उसका पालन-पोषण संस्कारों के बीच होता है। लिव-इन से पैदा होने वाले बच्चों के सामाजिक नाम और उनके अधिकारों पर आज भी प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।

भावनात्मक अस्थिरता: विवाह में प्रतिबद्धता अधिक होती है। लिव-इन में आसान निकास का विकल्प होने के कारण रिश्तों में गंभीरता की कमी देखी जाती है, जो अक्सर अवसाद या अपराध (जैसे हालिया कुछ आपराधिक घटनाएं) का कारण बनती है। भारतीय कानून (माननीय सर्वोच्च न्यायालय) ने लिव-इन रिलेशनशिप को अवैध नहीं माना है।

घरेलू हिंसा अधिनियम और संपत्ति के अधिकारों में लिव-इन पार्टनर्स को कुछ सुरक्षाएं दी गई हैं। लेकिन, कानूनी रूप से सही होना और सामाजिक रूप से स्वीकार्य होना, भारत में दो अलग बातें हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन अपनी जड़ों को काटकर किया गया परिवर्तन अक्सर विनाशकारी होता है। भारतीय संस्कार हमें त्याग और समर्पण सिखाते हैं, जबकि आधुनिक जीवनशैली अधिकार और स्वतंत्रता पर केंद्रित है।लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही है या गलत, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसे प्राथमिकता देते हैं- क्षणिक सुख और सुविधा को या दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता और संस्कारों को। एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि आधुनिकता के नाम पर हम उन मूल्यों को न खो दें जिन्होंने भारतीय सभ्यता को हजारों वर्षों से जीवित रखा है। लिव-इन रिलेशनशिप पर भारतीय न्यायपालिका का दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुआ है।अदालतों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। भारतीय न्यायालयों द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख और ऐतिहासिक फैसले दिए गए हैं, जिन्होंने इस विषय की कानूनी दिशा तय की:2013 इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी.सरमा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा और भरण-पोषण की हकदार है। वहीं 2015 के धन्नू लाल बनाम गणेशराम प्रकरण में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो कानून उन्हें पति-पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा और उनकी संतान को वैध माना जाएगा।

न्यायालयों ने लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी सुनिश्चित किए हैं- बच्चों की वैधता: लिव-इन संबंधों से पैदा हुए बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार है। कानून उन्हें अवैध नहीं मानता। भरण-पोषण- यदि रिश्ता टूटता है, तो महिला सीआरपीसी की धारा 125 (अब नई संहिता के तहत) या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। संपत्ति में अधिकार: केवल साथ रहने मात्र से महिला को पुरुष की पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, लेकिन पुरुष द्वारा अर्जित संपत्ति और वसीयत के आधार पर दावे किए जा सकते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू कर लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर सजा का प्रावधान है। यह इस दिशा में एक बड़ा मोड़ है, जहाँ राज्य अब सुरक्षा के नाम पर निजी रिश्तों में पारदर्शिता चाहता है। हालांकि कानून लिव-इन को मान्यता देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराया है कि लिव-इन पार्टनर को पत्नी का पूर्ण कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, जब तक कि वे औपचारिक विवाह न कर लें। स्पष्टता और पारदर्शिता किसी भी रिश्ते की शुरुआत ट्रेंड को देखकर नहीं, बल्कि आपसी समझ से होनी चाहिए। यदि आप लिव-इन में रहने का विचार कर रहे हैं, तो अपने साथी के साथ भविष्य के लक्ष्यों, वित्तीय जिम्मेदारी और उम्मीदों पर खुलकर बात करें। अस्पष्टता बाद में मानसिक तनाव का कारण बनती है। एक जागरूक युवा के रूप में आपको देश के कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को समझें ताकि आप और आपके साथी के अधिकारों की रक्षा हो सके। कानून का ज्ञान आपको असुरक्षा की भावना से बचाता है।अक्सर रिश्तों के शुरुआती उत्साह में युवा अपने करियर और व्यक्तिगत विकास को पीछे छोड़ देते हैं। याद रखें, आप पहले एक व्यक्ति हैं और फिर किसी के साथी। अपनी पढ़ाई, करियर और जुनून को प्राथमिकता दें। एक सफल और आत्मनिर्भर व्यक्ति ही एक स्वस्थ रिश्ता निभा सकता है। भारतीय संस्कार हमें सम्मान और संयम सिखाते हैं। भले ही आप एक आधुनिक जीवनशैली चुन रहे हों, लेकिन अपने साथी के प्रति वफादारी, सम्मान और गरिमा बनाए रखना अनिवार्य है। रिश्ते को केवल अपनी सुविधा का साधन न समझें, बल्कि उसे परिपक्वता से निभाएं।हो सकता है कि आपके माता-पिता या परिवार इस विचार से सहमत न हों। उनसे विद्रोह करने के बजाय, धैर्यपूर्वक संवाद करने का प्रयास करें। उन्हें अपनी स्थिति और सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करें। परिवार का समर्थन जीवन की बड़ी चुनौतियों में ढाल का काम करता है।

किसान संरक्षण, गुणवत्ता नियमन और वैश्विक कृषि शासन की दिशा में भारत का निर्णायक कदम

वर्तमान डिजिटल प्रतिस्पर्धा युग में वैश्विक अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ- साथ नकली और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का प्रसार भी एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। चाहे वह दवाइयाँ हों, खाद्य पदार्थ हों, कृषि आदान हों या तकनीकी उपकरण, नकली माल का उपयोग उपभोक्ताओं के लिए केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर भी गहरा प्रतिकूल प्रभाव डालता है।विडंबना यह है कि जहां एक ओर उपभोक्ता इस बहुआयामी क्षति को झेलता है, वहीं दूसरी ओर इस गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े तत्व भारी आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं। यही कारण है कि आज विश्व स्तरपर यह स्वीकार किया जा रहा है कि नकली उत्पादों से निपटने के लिए केवल सामान्य आपराधिक कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्षेत्र-विशेष के लिए विशेष और कठोर कानूनों की आवश्यकता है। मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि कृषि क्षेत्र में इस समस्या का प्रभाव और भी अधिक गहरा है,क्योंकि यहां नुकसान केवल एक उपभोक्ता तक सीमित न होकर खाद्य सुरक्षा,ग्रामीणअर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय कृषि प्रणाली तक फैल जाता है। नकली या घटिया बीजों का प्रयोग किसान की पूरी फसल,उसकी आय,ऋण चुकाने की क्षमता और अंततः उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यही पृष्ठभूमि है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बीज विधेयक, 2025 को ला रही है। यह एक ऐसा विधायी प्रयास जो न केवल नकली बीजों पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखता है,बल्कि किसानों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कृषि बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।बीज विधेयक, 2025 दरअसल 1966 के पुराने बीज अधिनियम का स्थान लेने के लिए लाया गया है, जो वर्तमान समय की जटिलताओं और बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप अपर्याप्त सिद्ध हो रहा था। पिछले कुछ दशकों में बीज उद्योग में निजी कंपनियों, हाइब्रिड और उन्नत किस्मों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और डिजिटल आपूर्ति श्रृंखलाओं का तीव्र विस्तार हुआ है, लेकिन नियामक ढांचा उसी अनुपात में विकसित नहीं हो सका। इस अंतर का लाभ उठाकर नकली बीजों का संगठित कारोबार फलता-फूलता रहा,जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नए विधेयक का मूल उद्देश्य इसी असंतुलन को सटीक रूप से दूर करना है। साथियों बात अगर हम बीज विधेयक,2025 को समझने की करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बीजों की गुणवत्ता को एक राष्ट्रीय मानक के अंतर्गत लाने का प्रयास करता है। विधेयक के अनुसार, बाजार में बेची जाने वाली सभी बीज किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक होगा। इसका अर्थ यह है कि कोई भी बीज, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विकसित हो या निजी कंपनियों द्वारा,बिना नियामक स्वीकृति के किसानों तक नहीं पहुंच सकेगा। यह प्रावधान नकली और अप्रमाणित बीजों के लिए बाजार के दरवाजे बंद करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।इसके साथ ही, विधेयक बीज उत्पादकों, बीज प्रसंस्करण इकाइयों, डीलरों और पौध नर्सरियों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। यह व्यवस्था पूरी आपूर्ति श्रृंखला को निगरानी के दायरे में लाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न हो।अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि कृषि आदानों में पारदर्शी ट्रैकिंग और पंजीकरण प्रणाली नकली उत्पादों को रोकने का सबसे प्रभावी साधन होती है, और इस दृष्टि से बीज विधेयक, 2025 भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के समकक्ष खड़ा करता है। साथियों बात अगर हम विधेयक को एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान से समझने की करें तो, आपातकालीन परिस्थितियों में बीज बिक्री मूल्यों का विनियमन है। प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तनजनित संकटों या महामारी जैसी स्थितियों में अक्सर बीजों की कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं।इसका सीधा बोझ किसान पर पड़ता है।बीज विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी असाधारण परिस्थितियों में बीजों की कीमतों को नियंत्रित कर सके, जिससे किसानों का शोषण रोका जा सके। यह प्रावधान कृषि को केवल बाजार की शक्तियों के हवाले न छोड़कर सामाजिक न्याय के सिद्धांत से जोड़ता है।बीजों के प्रदर्शन का अनिवार्य लेबलिंग भी विधेयक का एक केंद्रीय तत्व है। लेबलिंग के माध्यम से बीज की किस्म, अंकुरण क्षमता,शुद्धता, उत्पादन वर्ष और अन्य आवश्यक जानकारियाँ स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी और धोखाधड़ी की संभावना न्यूनतम होगी। वैश्विक स्तर पर यह माना जाता है कि सूचना की पारदर्शिता उपभोक्ता संरक्षण का सबसे मजबूत आधार है, और बीज विधेयक इसी सिद्धांत को कृषि क्षेत्र में लागू करता है।डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधेयक में 'साथी पोर्टल' पर अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान भी किया गया है। यह पोर्टल बीज से जुड़े सभी हितधारकों उत्पादकों डीलरों और नियामक एजेंसियों के बीच एक साझा डिजिटल मंच प्रदान करेगा। इससे न केवल निगरानी और शिकायत निवारण की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि नीति-निर्माण के लिए विश्वसनीय डेटा भी उपलब्ध होगा। अंतरराष्ट्रीय कृषि शासन में डेटा-आधारित नियमन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस दृष्टि से यह प्रावधान भारत को भविष्य के लिए तैयार करता है। साथियों बात अगर हम बीज विधेयक, 2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण आशंकाओं को समझने की करें तो,यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि कहीं यह किसानों की पारंपरिक प्रथाओं और अधिकारों को सीमित न कर दे। हालांकि विधेयक इस संदर्भ में अत्यंत स्पष्ट है। इसके प्रावधान किसानों और उनकी पारंपरिक किस्मों पर लागू नहीं होते।यह विधेयक पादप किस्मों के संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के अनुरूप किसानों के उन अधिकारों की रक्षा करता है, जिनके तहत वे बीजों को उगाने, बोने, सहेजने, आदान-प्रदान करने और बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।
यह संतुलन इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है।इसके अतिरिक्त, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और पादप किस्मों के संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पहले से ही किसानों, सामुदायिक बीज उत्पादकों और स्वदेशी किस्मों की सुरक्षा के लिए जो प्रावधानमौजूद हैं यह विधेयक उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसका अर्थ यह है कि बीज विधेयक,2025 किसीमौजूदा अधिकार को कमजोर नहीं करता, बल्कि नियमन और संरक्षण के बीच एक व्यावहारिक संतुलन बनाता है। साथियों बात अगर हम इस विधेयक को दंडात्मक प्रावधानों की दृष्टि से भी समझने की करें तो, यह विधेयक पुराने कानून की तुलना में अधिक प्रभावी है। नकली बीजों की बिक्री पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना और कारावास का प्रावधान न केवल एक निवारक प्रभाव उत्पन्न करता है,बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि कृषि क्षेत्र में धोखाधड़ी को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। वैश्विक स्तर पर कृषि इनपुट्स की गुणवत्ता को लेकर जो सख्ती अपनाई जा रही है, भारत का यह कदम उसी दिशा में है। साथियों बात अगर हम इस विधेयक को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो,बीज विधेयक, 2025 भारत को एक जिम्मेदार कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है।आज जब वैश्विक खाद्य सुरक्षा,जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दे केंद्र में है, तब बीजों की गुणवत्ता और उपलब्धता निर्णायक भूमिका निभाती है। यह विधेयक न केवल घरेलू किसानों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ाता है।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बीज विधेयक, 2025 नकली माल के खिलाफ भारत की व्यापक नीति का कृषि क्षेत्र में ठोस प्रतिबिंब है। यह विधेयक एक ओर किसानों को ठगी और नुकसान से बचाने का प्रयास करता है, तो दूसरी ओर कृषि बाजार में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता संस्कृति को मजबूत करता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है,तो यह न केवल किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक होगा,बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करेगा।
इस दृष्टि से बीज विधेयक, 2025 को केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत की कृषि नीति में एक संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

उदिषा साहित्योत्सव में खूब बिकी किताबें

मुरादाबाद ।

बुद्धि विहार स्थित गांधी मैदान में आयोजित उदीषा- 2026 चौपाला साहित्य उत्सव में आयोजित पुस्तक मेले में साहित्यिक मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद के साहित्यकार नाम से लगे स्टाल पर सर्वाधिक धनराशि प्रख्यात साहित्यकार डॉ राकेश चक्र की पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त हुई है। द्वितीय स्थान पर उर्दू साहित्य शोध केंद्र के संस्थापक साहित्यकार डॉ मोहम्मद आसिफ हुसैन रहे जबकि तृतीय स्थान पर युवा लेखिका 'योति कुमारी रहीं । डॉ मोहम्मद जावेद चौथे और डॉ जसदेव सिंह आनंद पांचवे स्थान पर रहे । भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा बाल साहित्य के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान बाल साहित्यश्री सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य की दीर्घकालीन सेवाओं के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान बाल साहित्य भारती से विभूषित मुरादाबाद के साहित्यकार डॉ राकेश चक्र की पुस्तकें ब'चों की मनोरंजक पहेलियां, ब'चों की ज्ञान वर्द्धक पहेलियां, ब'चों की प्रिय पहेलियाँ, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, मेरी प्रिय बाल कहानियाँ तथा जीत आपके हाथ में पाठकों द्वारा पसंद की गईं। इन पुस्तकों की बिक्री से दो हजार दो सौ पांच रुपये की धनराशि प्राप्त हुई जो उन्होंने साहित्यिक मुरादाबाद न्यास को प्रदान कर दी। मुरादाबाद के उर्दू साहित्य के इतिहास और विरासत को अपने लेखन के माध्यम से उजागर करने वाले साहित्यकारडॉ मोहम्मद

आसिफ हुसैन की पुस्तकें मुरादाबाद में गजल का सफर, मुरादाबाद के गैर मुस्लिम शायर तथा त'किरा शोरा ए मुरादाबाद (उर्दू) की बिक्री से दो हजार अस्सी रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। उन्होंने भी यह राशि साहित्यिक मुरादाबाद न्यास को प्रदान कर दी है। तीसरे स्थान पर ज्योति कुमारी रहीं। उनकी पुस्तक जादुई जंगल की कहानियां से एक हजार नौ सौ रुपये की राशि प्राप्त हुई जो कृति की लेखिका को प्रदान कर दी गई। इसके अतिरिक्त डॉ मनोज रस्तोगी द्वारा संपादित डॉ मोहम्मद जावेद की पुस्तक किस्से कहानियां की बिक्री से एक हजार सात सौ रुपये तथा डॉ जसदेव सिंह आनंद की पुस्तक तनाव से मुक्ति की बिक्री से एक हजार एक सौ नब्बे रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। पाठकों द्वारा डॉ प्रशांत भारद्वाज की पुस्तक एकादशी व्रत कथा, अशोक विश्नोई की सपनों का शहर, डॉ पूनम गुप्ता की सुंदर कांड गद्य रूप, डॉ जगदीश शरण की फूलन दि ग्रेट, अश्विनी प्रताप की प्रायश्चित, हर्ष अमरोही की कविता की परछाई, जिया जमीर की ये सब फूल तुम्हारे नाम, डॉ प्रेमवती उपाध्याय की आचरण की गंध, राजकुमार वर्मा की संक्षिप्त हिन्दू ज्ञान माला, डॉ कृष्ण कुमार नाज की व्याकरण गजल का, डॉ चन्द्र प्रकाश शर्मा की अमृतत्व की खोज पुस्तकें भी पाठकों द्वारा पसंद की गईं। स्टॉल पर मुरादाबाद मंडल के हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा के 76 साहित्यकारों की पुस्तकें प्रदर्शन/ बिक्री के लिए रखी गई थीं । पांच दिन में मुरादाबाद के साहित्यकारों की कुल 169 पुस्तकों की बिक्री हुई।

स्टॉल पर एमआई टी के चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर गुप्ता की पुस्तिका हिन्दू धर्म क्या है (हिन्दी व अंग्रेजी) तथा मुरादाबाद के साहित्यकार फक्कड़ मुरादाबादी की देशभक्ति गीतों की पुस्तिकाएं स्टॉल पर आए विद्यार्थियों और साहित्यप्रेमियों को निशुल्क भी वितरित की गई ।

टीएमयू में मैनेजमेंट, नर्सिंग और फाइनआर्टस कॉलेजों ने जीते दो-दो मुकाबले

चैंपियनशिप में यूनिवर्सिटी के 14 कॉलेजों की टीमें आजमाएगीं किस्मत

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के टिमिट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की ओर से आयोजित इंटरकॉलिजिएट चैंपियनशिप- 2026 के बैडमिंटन की प्रतियोगिता में मैनेजमेंट, नर्सिंग और फाइन आर्टस कॉलेजों ने 02-02 मुकाबले अपने नाम किए। चैंपियनशिप के फर्स्ट डे सिंगल्स, डबल्स और मिक्स के आठ मुकाबले हुए। फार्मेसी और लॉ कॉलेज ने भी एक-एक मुकाबले में जीत का स्वाद चखा। उल्लेखनीय है, टीएमयू की इस इंटरकॉलिजिएट चैंपियनशिप में क्रिकेट, फुटबाल, बास्केटबाल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बॉक्स क्रिकेट, टग ऑफ वार, एथलेटिक्स, कबड्डी, बेंच प्रेस, टेबल टेनिस, चेस, कैरम सरीखे 16 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। 24 फरवरी तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में यूनिवर्सिटी के 14 कॉलेजों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। टिमिट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की खुशी जैन ने वुमेन सिंगल्स में लॉ कॉलेज की प्राची यादव और मिक्स डबल्स के मुकाबले में मैनेजमेंट के अमन और खुशी जैन ने लॉ के शिखर और स्नेहा को 2-0 से मात दी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग और कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल के मैन सिंगल्स में नर्सिंग के रिभव प्रियदर्शिनी ने पैरामेडिकल के असीम उस्मानी को 2-0 से हराया। वुमेन सिंगल्स में नर्सिंग की तनवी सिंह ने पैरामेडिकल की रिद्धिमा भुवाना को 2-0 से पटखनी दी। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और कॉलेज ऑफ फार्मेसी के मैन सिंगल्स में फाइन आर्ट्स के आयुष ने फार्मेसी के प्रिंस और मिक्स डबल्स में फाइन आर्ट्स के आयुष और पायल ने फाइन आर्ट्स के अविनाश और सुहानी को 2-0 से मात दी। फार्मेसी कॉलेज की अंजलि ने वुमेन सिंगल्स के मुकाबले में की फाइन आर्ट्स की सुहानी को 2-0, जबकि लॉ कॉलेज के शिखर चौधरी ने मैनेजमेंट के चिन्मय जैन को मैन सिंगल्स के मुकाबले में 02 से पराजित किया।

टीएमयू फिजिकल एजुकेशन कॉलेजसे अनुभव गुप्ता को पीएचडी अवार्ड

Accredited with NAAC A Grade
12-B Status from UGC

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद से टिमिट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्टुडेंट अनुभव गुप्ता को यूनिवर्सिटी की ओर से पीएचडी की डिग्री अवार्ड की गई है। गुप्ता ने अनाथ बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर योग एवम् मनोरजक गतिविधियों का प्रभाव शीर्षक पर शोध किया है। गुप्ता ने यह शोध टिमिट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्राचार्य प्रो. मनु मिश्रा के मार्गदर्शन में किया है। उल्लेखनीय है, प्रो. मिश्रा के निर्देशन में अब तक सात पीएचडी हो चुकी हैं। पीएचडी अवार्डी गुप्ता के पिता श्री प्रदीप गुप्ता टीएमयू के एनिमेशन विभाग में 14 बरसों से बतौर टीचर तैनात हैं। बहुप्रतिभा के धनी श्री गुप्ता की झोली में अब तक छह इंडियन पेटेंट भी आ चुके हैं, जबकि अनुभव गुप्ता शहर के एक सीबीएसई स्कूल में बतौर प्रवक्ता तैनात हैं। गुप्ता ने बीपीएड और एमपीएड भी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से किया है। उल्लेखनीय है, गुप्ता ने दो टूल्स- इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल और एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस स्केल के जरिए मुरादाबाद शहर के 60 अनाथ बच्चों पर रिसर्च किया है। शोध अध्ययन में पाया गया, यदि इन अनाथ ब'चों को योग और मनोरजक संसाधन मुहैया कराएं जाएं तो इन्हें अपने अतीत से उबारा जा सकता है। और समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है। पीएचडी अवार्डी गुप्ता बताते हैं, शोध के दौरान इन बच्चों के लिए योग कैंप के संग-संग मनोरंजक गतिविधियां भी कराई गईं। एक रिसर्च के मुताबिक माता-पिता के अभाव में बच्चे गंभीर मानसिक, शारीरिक और विकासात्मक जोखिमों का सामना करते हैं। शोध के आंकड़े बताते हैं, ऐसे बच्चों में 21 प्रतिशत अवसाद, 45 प्रतिशत चिंता और 23 प्रतिशत निम्न आत्मसम्मान की उच्च दर पाई जाती हैं, लेकिन इस शोध के जरिए यह प्रमाणित हुआ, योग कैंप, मनोरंजक गतिविधियां यदि नियमित रूप से हों तो अवसाद, चिंता आदि के आंकड़ों में कमी आने की प्रबल संभावना है।

केवाईसी, आधार एंव एसआईआर मतदाता सूची में शुद्धिकरण के पीछे ग्राहकों , नागरिकों एंव मतदाताओं को करनी पड रही है जेब ढीली, पर जिम्मेदार बने हुए लापरवाह

मेंहदावल, संतकबीर नगर। मेंहदावल क्षेत्र के ग्राहकों , नागरिकों एंव मतदाताओं को केवाईसी, आधार व एस आई आर के तहत मतदाता सूची में शुद्धिकरण के पीछे दर-दर भटकने पर हो रहे हैं परेशांहाल ! तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार बने हुए हुए हैं लापरवाह, जेब ढीली करने के बाद भी दर-दर भटकने पर मजबूर हैं उक्त जन ! जी हां हम बात कर रहे हैं केवाईसी, आधार, तथा एस आई आर के तहत मतदाता सूची में शुद्धिकरण कराने के लिए फोटो स्टेट, आधार, पैन कार्ड, केवाईसी, जाति, निवास, जन्म प्रमाण- पत्र, परिवार रजिस्टर आदि को प्राप्त करने के लिए लोगों को एक ओर जहां भारी भरकम धनराशि नागरिकों को जेब ढीली करने पर मजबूर होना पड रहा है, उसके बाद भी दफ्तर दफ्तर दौड़ लगाने पर मजबूर होना पड रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिचौलियों से लेकर जिम्मेदार भी हो रहे हैं मालामाल फिर भी बने हुए है मूक एंव गैर जिम्मेदार ! ऐसी स्थिति देखी गयी सोमवार भारतीय उप डाकघर मेंहदावल कार्यालय पर आधार कार्ड में नाम संशोधन कराने हेतु पिछले एक माह से दौड़ लगा रहे मोहम्मद अमजद निवासी बारागदी जो परेसांहाल दिखा , मोहम्मद अमजद ने संवाददाता को बताया कि डाक कर्मचारी द्वारा सही जानकारी न देकर तहसील से निवास प्रमाण पत्र बनवाने को कहा गया था, जबकि सबसे पहले आधार कार्ड में हमने नाम संशोधन करने के लिए उक्त महोदय से कहा गया था, संशोधन करने से पहले भेज दिया गया तहसील निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, निवास प्रमाण पत्र में मोहम्मद अमजद की जगह मो, अमजद फीड कर निवास प्रमाण -पत्र आधार के तर्ज पर बनाकर दे दिया गया है, जो बाद में कैंसिल का भी मैसेज दे रहा है, अब हमें एफिडेविट के साथ अखबार में गजट कराने को कहा जा रहा है, वह भी जनपद गोरखपुर जाकर सुधार कराने के लिए भेजा जा रहा है, जबकि इससे पहले एक माह तक हमें हमारे नाम में मात्र मो, अमजद की जगह नाम मोहम्मद में पूरा शब्द मोहम्मद अमजद ही कराना है , जबकि जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड मे मेरा नाम मोहम्मद अमजद के नाम पहले से ही मौजूद है, मात्र आधार कार्ड में मोहम्मद अमजद कराना था, पर डाक कर्मचारी के गैर जिम्मेदारना व्यवहार और आर्थिक क्षति पहुंचाने के बाद भी उक्त प्रकार का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है ! जबकि हमें पासपोर्ट बनवाने में आधार कार्ड में नाम संशोधन कराऐ जाने की आवश्यकता थी / है ! उक्त समय मौजूद संवाददाता के सामने जब मोहम्मद अमजद द्वारा मात्र मोबाइल से एक फोटो खींचना चाहा गया, उक्त कर्मचारी द्वारा मोबाइल छीनकर उप डाक अधिकारी महोदय को दे दिया गया, और यह कहा गया कि वीडियो बना रहे हो पुलिस बुलाकर कार्रवाई करा दूंगा।

दो दिवसीय तहसील स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन

मेजा,प्रयागराज।

तहसील क्षेत्र में आयोजित दो दिवसीय तहसील स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन आज उत्साह और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन खिलाड़ियों में खासा जोश देखने को मिला। फाइनल मुकाबला दर्शकों के लिए रोमांचक रहा, जिसमें दोनों टीमों ने जीत के लिए कड़ा संघर्ष किया। प्रतियोगिता में तहसील के विभिन्न गांवों और क्षेत्रों से आई टीमों ने भाग लिया। पहले दिन से ही खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन और टीम वर्क का परिचय दिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना, छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना तथा स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देना रहा। फाइनल मुकाबले में आदर्श क्लब अरई और सुदिष्ट इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा खेला गया जिसमें विजेता रही सुदिष्ट इंटरप्राइजेज की टीम।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि मेजा प्रभारी दीनदयाल व साथ में एसडीएम मेजा द्वारा विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि इससे अनुशासन, नेतृत्व और आपसी सहयोग की भावना भी विकसित होती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होना सराहनीय है और इससे भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभर सकते हैं।

फाइनल मुकाबले में विजेता टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि उपविजेता टीम ने भी दमदार खेल दिखाकर दर्शकों की तालियां बटोरीं। प्रतियोगिता के अंत में विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए गए। आयोजन रमेश पांडे,श्री प्रकाश द्विवेदी कृष्ण प्रकाश द्विवेदी राकेश सिंह मुकेश सिंह करण सिंह, विजय सिह लोगों उपस्थित रहे विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उपस्थित रहे पूर्व खिलाड़ी राम सिंह टीएन सिंह आयोजन कों ने सफल आयोजन के लिए सभी खिलाड़ियों, निर्णायकों, दर्शकों और सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। समापन के साथ ही क्षेत्र में खेल गतिविधियों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। प्रतियोगिता ने युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया।

दिल्ली के कनॉट प्लेस में तीन डिलीवरी बॉय ने एक कारोबारी की हेलमेट से पीट- पीटकर की हत्या

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां देर रात पार्टी में गए 36 साल के कारोबारी शिवम गुप्ता की कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि खाना डिलीवरी करने वाले कुछ युवकों ने एक मामूली कहासुनी के बाद शिवम के सिर पर हेलमेट से बेरहमी से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना के बाद उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार शिवम गुप्ता की मौत 19 जनवरी को हुई है लेकिन इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी अब हुई है. पुलिस ने अभी तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है. पुलिस सूत्रों से मिली

जानकारी के अनुसार 3 जनवरी की रात पीसीआर पर सूचना मिल थी कि एक शख्स कनॉट प्लेस के ई ब्लॉक में घायल हालत में पड़ा हुआ है. पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची थी शख्स की हालत बेहद खराब थी. उसे फौरन लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां बाद में उसकी पहचान शिवम गुप्ता के रूप में की गई. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सिर में कई गंभीर अंदरूनी चोटें (हेमाटोमा) पाईं और शिवम को बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. बाद में पुलिस ने बेहतर इलाज के लिए शिवम को 4 जनवरी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल शिफ्ट किया. जहां 5 जनवरी को शिवम गुप्ता की सर्जरी हुई. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शिवम गुप्ता के पिता ने बताया कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि चोटें जानलेवा है. ऑपरेशन के बाद 36 से 72 घंटे बेहद अहम है. कुछ वक्त के लिए उम्मीद जगी थी, वह डॉक्टरों की आवाज पर प्रतिक्रिया भी दे रहा था लेकिन 19 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया. परिवार का आरोप है कि करीब तीन लोगों ने मिलकर शिवम के सिर पर बार-बार हेलमेट से वार किया. इस घटना को लेकर शिवम के एक रिश्तेदार ने कहा बताया कि वह पार्टी में गया था, लेकिन वापस जिंदा नहीं आया. वहीं, इस मामले में अभी पुलिस की जांच जारी है. पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना सामान जब्त किया है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है. शुरुआती तौर पर मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 3(5) (साझा इरादा) के तहत दर्ज किया गया है. सूत्रों के मुताबिक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया गया है.

बोलने से रोकना लोकतंत्र पर कलंक; राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

नई दिल्ली।कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से उन्हें रोकना लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा को रोकने का प्रयास है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा "कल जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोल रहा था, तो आपने मुझे उस पत्रिका की प्रामाणिकता सत्यापित करने को कहा, जिसका मैं हवाला देना चाहता था। मैंने आज अपने भाषण की शुरुआत में दस्तावेज को प्रमाणित कर दिया। परंपरा के अनुसार, एक सदस्य जो किसी दस्तावेज का हवाला देना चाहता है,

उसे उसका प्रमाणिकरण करना होता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद स्पीकर सदस्य को दस्तावेज का हवाला देने की अनुमति देते हैं। इसके बाद इसका जवाब सरकार की जिम्मेदारी होती है और अध्यक्ष का कर्तव्य समाप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा मुझे लोकसभा में बोलने से रोकना केवल इस परंपरा का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि विपक्ष के नेता के रूप में मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर बोलने से रोकने का जानबूझकर प्रयास किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुख्य विषय था, जिस पर संसद में चर्चा होना आवश्यक है। राहुल गांधी ने स्पीकर को याद दिलाया कि संसद में सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना उनकी संवैधानिक और संसदीय जिम्मेदारी है। उन्होंने लिखा कि विपक्ष के नेता और हर सदस्य को बोलने का अधिकार लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह के अधिकारों से वंचित किए जाने की वजह से संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जब सरकार के कहने पर स्पीकर ने विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोका। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर कलंक बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा राष्ट्रपति के भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। पाकिस्तानियों, चीनियों और हमारे बीच के संबंध। इस लेख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी मैंने पुष्टि की है। यह प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया के बारे में बात करता है... हमारे राष्ट्रपति का भाषण उस मार्ग के बारे में था जिस पर भारत को आज चलना है। विश्व मंच पर, अंतरराष्ट्रीय मामलों का मुख्य मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष है। यह हमारे राष्ट्रपति के भाषण का केंद्र बिंदु है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे चीन और भारत के बीच जो हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, उस पर एक बयान देने दीजिए।

मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा- एअर इंडिया और इंडिगो के विमान के पंख टकराए, सभी यात्री सुरक्षित

मुंबई ।मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार को बड़ा विमान हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरे दो विमानों के बीच जमीन पर टक्कर हो गई। घटना रनवे और टैक्सीवे क्षेत्र में हुई, जहां एक विमान खड़ा था और दूसरा लैंडिंग के बाद आगे बढ़ रहा था। राहत की बात यह रही कि इस टक्कर में कोई यात्री घायल नहीं हुआ और सभी सुरक्षित है।

सूत्रों के अनुसार एअर इंडिया की फ्लाइट एआई 2732 मुंबई से कोयंबटूर जाने के लिए टैक्सीवे पर खड़ी थी। उसी समय इंडिगो की फ्लाइट 6ई 791 हैदराबाद से मुंबई पहुंचने के बाद टैक्सी कर रही थी। इसी दौरान आगे बढ़ते इंडिगो विमान का पंख खड़े एअर इंडिया विमान के पंख से टकरा गया। टक्कर जमीन पर हुई, उड़ान के दौरान नहीं। एअर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक घटना 3 फरवरी को टेक-ऑफ से पहले इंतजार के दौरान हुई। दोनों विमानों के विंगटिप्स यानी पंख आपस में

टकराए। इससे एअर इंडिया के विमान के पंख के किनारे वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा। टक्कर हल्की थी, लेकिन सुरक्षा नियमों के तहत इसे गंभीरता से लिया गया है। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा टीम सक्रिय हो गई। प्रभावित विमान को तुरंत ग्राउंडेड कर दिया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया। एअर इंडिया ने यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की। दोनों विमानों को तकनीकी जांच के लिए सेवा से बाहर रखा गया है। एयरलाइन की ओर से बताया गया कि घटना की सूचना एविएशन रेगुलेटर को दे दी गई है। तकनीकी टीम दोनों विमानों की विस्तृत जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी यात्री या क्रू मेंबर के घायल होने की खबर नहीं है। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद तय होगी। एयरपोर्ट संचालन कुछ समय प्रभावित रहा, लेकिन बाद में सामान्य कर दिया गया। इंडिगो एयरलाइंस ने भी बयान जारी कर हादसे की पुष्टि की है। इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, 3 फरवरी 2026 को हैदराबाद से मुंबई जाने वाली हमारी फ्लाइट 6ई 791 के एक एयरक्राफ्ट का विंगटिप, लैंडिंग के बाद टैक्सी करते समय, दूसरी एयरलाइन के एक एयरक्राफ्ट से टकरा गया। सभी यात्री सुरक्षित है और पार्किंग के बाद उतर गए। एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तय प्रोटोकॉल के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

बीजेपी का मिशन 100, पीएम मोदी की मेंगा रैली

इस रणनीति के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को गुवाहाटी का दौरा करेंगे, जहां वे असम भर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के एक विशाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

असम। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने असम में 100 सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो राज्य में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए पार्टी के दृढ़ संकल्प का संकेत है। इस रणनीति के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को गुवाहाटी का दौरा करेंगे, जहां वे असम भर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के एक विशाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में लगभग एक लाख बूथ स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे, जो पार्टी की मजबूत जमीनी उपस्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 फरवरी को असम का दौरा करने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान, गृह मंत्री महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकें करेंगे, चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे और भाजपा की चुनाव प्रचार रणनीति को मजबूत करने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की यात्राओं से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश आएगा और उन्हें स्पष्ट रणनीतिक दिशा मिलेगी। भाजपा का लक्ष्य असम भर में विकास, सुशासन और मजबूत संगठनात्मक पहुंच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। असम में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा कांग्रेस के खिलाफ अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है। सोमवार को असम में, जहां चुनाव होने वाले है, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कामरूप (मेट्रो) जिले के सोनापुर में आयोजित एक केंद्रीय कार्यक्रम में एसएसआईडीएस, पीएम-दिव्य और आरआईडीएफ-एक्सएक्सएक्सएक्स के तहत निर्मित 67 अत्याधुनिक विद्यालय भवनों का उद्घाटन किया और आरआईडीएफ-एक्सएक्सआई के तहत असम के विभिन्न जिलों में बनने वाले 61 अन्य विद्यालयों की आधारशिला रखी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं में कुल निवेश 760 करोड़ रुपये है, क्योंकि इस पहल का उद्देश्य विश्व स्तरीय शिक्षण वातावरण तैयार करना है जो प्रत्येक बच्चे को बड़े सपने देखने और अधिक हासिल करने के लिए सशक्त बनाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए, हिमंता ने इस दिन को असम के शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने असम भर में 1,318 विद्यालयों के लिए नए भवनों का निर्माण शुरू किया है।

लोकसभा में कागज उछालने वाले आठ सांसद पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित

नई दिल्ली ।

सदन की कुर्सी पर कागज़ फेंकने के आरोप में आठ लोकसभा सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सांसदों में मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, किरण कुमार रेड्डी, एस वेंकटेशन, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस और प्रशांत पाडोले शामिल हैं। इनमें से सात सांसद कांग्रेस पार्टी से हैं, जबकि वेंकटेशन सीपीएम से हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक तीन बार स्थगित होने के बाद अपराह्न तीन बजे शुरू हुई तो पीठासीन

सभापति दिलीप सैकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, गुरदीप सिंह औजला,हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर तथा माकपा सांसद एस वेंकटेशन के नाम लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने आठों सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास आकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सदस्यों को नियम 374 (2) के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने सदन में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप कागज उछालकर फेंके थे। राहुल गांधी ने मंगलवार को सदन में

लोकसभा में राहुल के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हंगामा

नरवणे पर आर्टिकल दिखाया, तो स्पीकर ने रोका

नरवणे की पुस्तक पर आधारित लेख को सत्यापित करते हुए सदन के पटल पर रखा। उन्होंने फिर से नरवणे के संस्मरण और चीन के साथ टकराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका चीन तथा पाकिस्तान के साथ संबंध है और यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रमुख हिस्सा है। आसन से उन्हें आगे बोलने की अनुमति नहीं दी गई।

आई-पैक रेड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आई-पैक से जुड़े ईडी रेड विवाद में सुनवाई 10 फरवरी तक के लिए टाल दी है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उसने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। ईडी का कहना है कि जनवरी में जब वह कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आई-पैक कार्यालय पर छापेमारी कर रही थी, तब मुख्यमंत्री वहां पहुंचीं और अधिकारियों के काम में बाधा डाली। एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हटाए गए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल किया है और समय मांगा है, जिसके बाद अदालत ने अगली तारीख तय की। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले को गंभीर बता चुका है और ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा चुका है।

जम्मू -कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों में मुठभेड

ऊधमपुर । जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार, ऊधमपुर जिले के रामनगर के जोफर इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक, मौके पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सूत्रों ने बताया कि इलाके में अज्ञात आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस ऑपरेशन में SOG जम्मू-कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। मौके पर रुक-रुक कर फायरिंग जारी है और सुरक्षा बल आतंकियों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी नुकसान या गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों और सुरक्षित स्थानों में रहें।

ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले एसआईआर कराने पर उठाए सवाल, बोलीं- असम को क्यों छोड़ा गया?

नईदिल्ली। एसआईआर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल में इसे लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। इसी बीच नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (स्क्रूक) प्रक्रिया को लेकर केंद्र और चुनाव तंत्र पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं दिया जा रहा। ममता बनर्जी ने इसे चुनाव से ठीक पहले की गई संदिग्ध कार्रवाई बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोग एसआईआर प्रक्रिया के पीड़ित हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनके अनुसार कई वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों को न तो ठीक से सूचना दी जा रही है और न ही उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिल रहा है।

ममता बनर्जी ने उठाए ये सवाल

चुनाव से ठीक पहले एसआईआर प्रक्रिया क्यों शुरू की गई?

इतनी बड़ी जांच दो-तीन महीने में बिना पहले से योजना के कैसे पूरी की जा सकती है?

चार चुनावी राज्यों में से तीन में एसआईआर हो रहा है, लेकिन भाजपा शासित असम में क्यों नहीं?

एसआईआर के कथित पीड़ितों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा।

कई लोग एसआईआर से प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में लोग इससे परेशान भी है।

चुनाव से पहले समय पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने एसआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों शुरू की गई। उन्होंने पूछा कि क्या इतनी बड़ी जांच बिना लंबी तैयारी के दो-तीन महीने में पूरी की जा सकती है। उनके मुताबिक इससे चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं और मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनती है।

भाजपा शासित राज्य का भी किया जिक्र

ममता बनर्जी ने कहा कि चार चुनावी राज्यों में से तीन में एसआईआर किया जा रहा है, लेकिन भाजपा शासित असम में यह प्रक्रिया नहीं हो रही। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण करार दिया। उनका आरोप है कि विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाकर यह कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने चुनाव आयोग पर भी भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया।

चुनाव आयोग से मुलाकात और विरोध

उन्होंने बताया कि एक दिन पहले वह प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गई थीं और एसआईआर से प्रभावित लोगों को भी साथ ले गईं। ममता बनर्जी का कहना है कि बैठक के दौरान उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ, जिसके विरोध में उन्होंने बैठक छोड़ दी। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया।

पीड़ितों को न्याय दिलाने का दावा

ममता बनर्जी ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वे वास्तविक नागरिक हैं और लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी ऐसे लोगों की कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मताधिकार की रक्षा के लिए यह अभियान जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन भी होगा।

कोलकाता समेत पूर्वी भारत में भूकंप के झटके, म्यांमार रहा केंद्र; तीव्रता 6.0 दर्ज

कोलकाता। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मंगलवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे आम लोगों में अफरा-तफरी मच गई। भूकंप के झटके इतने स्पष्ट थे कि कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। फिलहाल किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूकंप के झटके रात करीब 9:04 बजे महसूस किए गए। कोलकाता के अलावा हावड़ा और हुगली जिलों में भी धरती कांपती हुई महसूस की गई। इतना ही नहीं, उत्तरी बंगाल के कई हिस्सों में भी भूकंप का असर देखा गया। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, इस भूकंप का केंद्र म्यांमार में स्थित था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र म्यांमार के अक्याब से करीब 70 मील पूर्व में था और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी। भूकंप का केंद्र अक्षांश 20.42 उत्तर और देशांतर 93.88 पूर्व पर स्थित था, जिसकी गहराई मुख्य रूप से 27 किलोमीटर बताई गई है। कुछ

जगहों पर 10 किलोमीटर से 63 किलोमीटर तक रिपोर्ट की गई है। भूकंप का मुख्य क्षेत्र म्यांमार (बर्मा) में है, विशेष रूप से राखाइन राज्य के निकट, जहां सित्तवे (एक्याब) से लगभग 70-100 किलोमीटर पूर्व या उत्तर दिशा में, एन टाउन के आसपास का इलाका प्रभावित रहा। इस भूकंप के झटके केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। बांग्लादेश और उत्तर-पूर्वी भारत के कई इलाकों में भी तेज कंपन महसूस किया गया, जिससे लोग सतर्क हो गए। पिछले 71 घंटों में म्यांमार में इस तीव्रता का यह तीसरा भूकंप है। म्यांमार भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जिसका असर आसपास के देशों तक महसूस किया जाना असामान्य नहीं है।

भाजपा जवाब दे, किसके दबाव में फिर किसानों पर वार किया- अखिलेश यादव

लखनऊ । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत-अमेरिका व्यापार सौदे को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों को खोलना देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी के साथ विश्वासघात है, जो खेती पर निर्भर है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने फिर किया किसानों पर वार, भाजपा सरकार दे जवाब, क्या है दबाव। उन्होंने आरोप लगाया, भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों व खाद्यान्नों के लिए खोल देना, हमारे देश की खेती-किसानी पर रोज़ी-रोजगार करने वाली 70 प्रतिशत आबादी के साथ धोखा है। सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए यादव ने दावा किया, भाजपाई और उनके संगी-साथी आजादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी हैं। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात करने वाले भाजपाई और उनके संगी-साथी जनता के बीच जाकर बताएं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ

धोखा करने के लिए कितना कमीशन खाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आशंका जताते हुए कहा, इससे केवल किसान ही नहीं, निम्न मध्यवर्ग और मध्यम वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होगा क्योंकि इससे खाद्यान्न और कृषि उत्पादों की मुनाफ़ाखोरी व बिचौलियों की एक नयी जमात पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से खाने-पीने की सब चीज़ें और भी महंगी हो जाएंगी। साथ ही भाजपा इन कंपनियों से चंदा वसूली भी करेगी, जिससे खाद्य व कृषि उत्पाद और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि इससे धीरे-धीरे हमारे किसानों की खेती बाड़ी और आय कम हो जाएगी और वे मजबूर होकर अपनी जमीन अमीरों व कॉर्पोरेट को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। जमीनों पर कब्ज़ा करना ही भाजपाई और उनके संगी-साथियों का आखिरी मकसद है। प्रस्तावित बीज विधेयक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय खेती के लिए घातक सीड बिल उसी कृषि और किसान विरोधी भाजपा सरकार की दिमागी उपज है जो भू अधिग्रहण और काले-कानून लाई थी। जो हर साल खाद की लाइन में लोगों को लगाकर उनको अपमानित करती है। उन्होंने आरोप लगाया, ये भाजपाई पहले बीज कंपनियों से कमीशन खाएंगे, फिर कीटनाशक कंपनियों से, फिर महा भंडारण के लिए बनने वाले साइलो की कंपनियों से, फिर फसल बीमा कंपनियों से, फिर कम कीमत तय करते समय।